भाजपा

भारतीय जनता पार्टी

कार्यालय: 6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110002 दूरभाष: 011-23500000

भाजपा

साफ नीयत सही विकास

साफ नीयत सही विकास

अमित शाह

अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी

प्यारे भाइयो एवं बहनों,

हमारी पार्टी की जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा और हमारा राजनीतिक उद्देश्य अन्य पार्टियों से अलग है।

हम '**अंत्योदय**' और '**भारत गौरव**' के लिए राजनीति में हैं।

हमने हर गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठाकर, उसको देश के नागरिक होने का अहसास कराया है और '**भारत**' हमारे देश का गौरव दुनिया में सबसे ऊपर स्थित करना, यह दो हमारे उद्देश्य हैं।

चार वर्ष पूर्व **श्री नरेन्द्र मोदी जी** के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने देश के समग्र विकास की प्रतिबद्धता के साथ अपना कार्य प्रारम्भ किया था।

आज मुझे यह कहने में हर्ष और गौरव की अनुभूति होती है कि एनडीए सरकार ने भारत की शासन व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की शुरुआत की है। मुख्यत: विकास ने अब एक आन्दोलन का रूप धारण कर लिया है और समाज के हर वर्ग का व्यक्ति अब इस विकास क्रम में भागीदार बन रहा है। मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं से देश के **22 करोड़ परिवार** लाभान्वित हो रहे हैं और आज विश्व में देश के गौरव में वृद्धि हुई है।

भाजपा को सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि लोगों के प्रति सेवा भाव से काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा देश और सभी भारतवासी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। अत: हमारे सभी निर्णय वोट पाने के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में एनडीए सरकार ने, हमने लोगों को **अच्छे लगें ऐसे फैसले नहीं लिये, लोगों के लिए अच्छे हों, ऐसे फैसले लिये हैं।**

भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। यही कारण है कि प्रत्येक भारतवासी के मन में भाजपा के लिए प्रेम और विश्वास का भाव जगा है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामाख्या तक भाजपा सबसे लोकप्रिय पार्टी है। आज हम देश के अनेक राज्यों में सत्ताधारी दल हैं। यह भाजपा का सौभाग्य है कि हमें देश के हर हिस्से से स्नेह मिला है। हम यह विश्वास दिलाते हैं कि अपने सभी देशवासियों के अभूतपूर्व प्यार प्रेम का प्रतिफल, राष्ट्र के अद्वितीय विकास से चुकाते रहेंगे।

यह प्रपत्र हमारी सरकार के पिछले चार वर्षों में किए गए अथक प्रयासों का लेखा जोखा है। हमारी '**साफ़ नीयत और सही विकास**' की दृष्टि के द्वारा आज देश के गरीब, शोषित और वंचित वर्ग के जीवन में व्यापक बदलाव आया है।

अभी काफी कुछ करना बाकी है, जिसके लिए **श्री नरेन्द्र मोदी जी** के नेतृत्व में हम कटिबद्ध हैं।

आपके **आशीर्वाद** की अपेक्षा सहित।

वन्दे मातरम्।

आपका

(अमित शाह)

भाजपा

समृद्ध किसान, सशक्त भारत

साफ नीयत
सही विकास

किसानों की आय दोगुनी करने का बहुआयामी लक्ष्य

- "प्रति बूंद अधिक फसल" का लक्ष्य हासिल करने के लिए - पर्याप्त बजट के साथ सिंचाई पर विशेष फोकस
- प्रत्येक खेत की मिट्टी की सेहत के आधार पर गुणवत्तापूर्ण बीजों और पोषक तत्वों का प्रावधान
- फसल कटाई के बाद पैदावार का नुकसान रोकने के लिए वेयर हाउसिंग और कोल्ड चेन्स में व्यापक निवेश
- खाद्य प्रसंस्करण के जरिए मूल्य संवर्धन को बढ़ावा
- राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण, विकृतियां दूर करना और 585 स्थानों पर ई-प्लेटफार्म की स्थापना
- किफायती लागत पर जोखिम कम करने हेतु एक नई फसल बीमा योजना की पेशकश
- पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन जैसी सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहन।

2017-18 में रिकॉर्ड उत्पादन (अनुमानित)

अनाज का उत्पादन:
277.49 मिलियन टन

चावल का उत्पादन:
111.01 मिलियन टन

मोटे अनाज का उत्पादन:
45.42 मिलियन टन

दालों का उत्पादन:
23.95 मिलियन टन

गन्ने का उत्पादन:
352.23 मिलियन टन

बागवानी उत्पादन
305.4 मिलियन टन

रिकॉर्ड नतीजे के लिए रिकॉर्ड बजट

- बजटीय आवंटन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी - 2009-2014 की अवधि के 1,21,082 करोड़ रुपये की तुलना में 2014-2019 की अवधि में खेती के लिए बजटीय आवंटन बढ़ा कर 2,11,694 करोड़ रुपये किया गया
- कृषि ऋण लक्ष्य: 2018-19 के लिए बढ़ा कर 11 लाख करोड़ रुपये किया गया
- कृषि बाजार ढांचा कोष: 2,000 करोड़ रुपये के साथ कृषि बाजार ढांचा कोष की स्थापना
- राष्ट्रीय बांस मिशन: बांस क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना में सहायता करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए 1,290 करोड़ रुपये का प्रावधान
- कर प्रोत्साहन:फसल कटाई परवर्ती कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करों में रियायत
- मत्स्य पालन, जलजीव पालन और पशुपालन क्षेत्रों में ढांचा निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष की स्थापना

किसानों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण

- ब्याज सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को एक वर्ष की अवधि के लिए तीन लाख रुपये तक के ऋण सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिए जाते हैं
- देशभर में 31 मार्च, 2017 तक 24.53 लाख संयुक्त देयता समूहों को बैंकों द्वारा 26,848.13 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए

न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और रिकॉर्ड ख़रीद के जरिए किसानों को अभूतपूर्व समर्थन

- किसानों को खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुणा अधिक मिलेगा
- दालों का सुरक्षित भंडार 1.5 लाख टन से बढ़ा कर 20 लाख टन किया गया
- करीब 16.24 लाख मेट्रिक टन दालों की खरीद (22.03.2018 तक) की गई।

उर्वरक अब हमेशा उपलब्ध

- यूरिया की शत-प्रतिशत नीम कोटिंग से धरती की सेहत में सुधार, कीटों और बीमारियों के हमलों में कमी
- इससे नाइट्रोजन के सक्षम उपयोग और फसल पैदावार में बढ़ोतरी हुई
- 2016-17 की बकाया उर्वरक सब्सिडी के भुगतान के लिए 2017-18 के बजट में रुपये 10,000 करोड़ विशेष बैंकिंग व्यवस्था के रूप में अनुमोदित किए गए
- नई यूरिया नीति अपनाने के बाद यूरिया के उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई
- डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों के एमआरपी में कमी आई
- गोरखपुर, सिंदरी, तलचर, रामागुंडम और बरौनी में बंद उर्वरक कारखानों को बहाल करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के निवेश का फैसला। नामरूप में मैसर्स ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत 8.4 एलएमटी प्रतिवर्ष क्षमता वाले नए यूरिया प्लांट की स्थापना की जाएगी

मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसानों को सूचित करने वाली पहलें

- 12.5 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए

कम दर वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को बड़ी राहत

- फसल बीमा में केंद्र सरकार द्वारा अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता
- रुपये 1,31,519 करोड़ की बीमा राशि के साथ 4.05 करोड़ किसान कवर किए गए और 379.06 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलों का बीमा किया गया

ई-नाम के जरिए उपज का सही मूल्य दिलवाने में किसानों की सहायता

- ई-व्यापार मंचों से 585 नियमित मंडियों को एकीकृत करके किसानों को अपनी उपज का सर्वाधिक दाम हासिल करने में मदद की गई
- इस प्लेटफार्म पर 87.5 लाख से अधिक किसान और विक्रेता पंजीकृत हैं
- ई-नाम प्लेटफार्म पर 41,591 करोड़ रुपये मूल्य के 164.53 लाख टन कृषि जिंसों का व्यापार किया गया

24X7 किसान चैनल

- किसानों को समर्पित 24X7 किसान टीवी चैनल की शुरुआत की गयी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करना

- पी.एम.के.एस.वाई के अंतर्गत 28.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था
- 'हर खेत को पानी' का लक्ष्य हासिल करने के लिए 5 वर्ष में 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
- 5,000 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध लघु सिंचाई कोष की स्थापना
- 2014-18 की अवधि में 26.87 लाख हेक्टेयर भूमि लघु सिंचाई के अंतर्गत लाई गई
- केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए सोलर वॉटर पंप लगाने में मदद करेगी

2014-18 की अवधि में 26.87 लाख हेक्टेयर भूमि लघु सिंचाई के अंतर्गत लाई गई

12.5 करोड़ से अधिक
मृदा स्वास्थ्य कार्ड
वितरित किए गए

कृषि बाजार ढांचा कोषः 2,000 करोड़ रुपये के साथ कृषि बाजार ढांचा कोष की स्थापना

बेहतर आय के लिए मूल्य संवर्धन और सही आपूर्ति श्रृंखला

- कृषि क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का शुभारंभ
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृषि सम्पदा योजना के तहत बजट आवंटन दोगुना किया गया
- ऑपरेशन ग्रीन्सः खराब होने वाली वस्तुओं जैसे टमाटर, प्याज और आलू (टी.ओ.पी) के मूल्यों में उतार- चढ़ाव की चुनौती का समाधान करने में किसानों एवं उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए अभियान
- ग्रामीण कृषि मंडियाः मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि मंडियों के रूप में विकसित और उन्नत बनाया गया ताकि 86 प्रतिशत से अधिक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की देखरेख की जा सके। ई-नाम के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़ी ये ग्रामीण कृषि मंडियां किसानों को अपना माल सीधे उपभोक्ताओं और बल्क खरीदारों को बेचने की सुविधा प्रदान करेंगी

खेती को नई मजबूती देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना

- 2015-18 की अवधि में कार्बनिक खेती के अंतर्गत 10,000 क्लस्टरों के जरिए दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया

नील क्रांति से किसानों के लिए नए आयाम खुले

- 3,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'मत्स्य उद्योग का एकीकृत विकास और प्रबंधन'
- मछली उत्पादन 2012-14 की अवधि के 186.12 लाख टन से बढ़कर 2014-16 के दौरान 209.59 टन पर पहुंचा

राष्ट्रीय गोकुल मिशन से दुग्ध उत्पादन और किसानों की आय में इजाफा

- वार्षिक औसत दुग्ध उत्पादन जो 2011-14 की अवधि में 146.33 मिलियन टन था, वह लगभग 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2014-17 की अवधि में 163.7 मिलियन टन पर पहुंच गया
- दिसम्बर 2014 में 500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शुरु किए गए राष्ट्रीय दुधारूपशु प्रजनन और डेरी विकास कार्यक्रम के तहत देसी दुधारूपशु प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के नए उपाय किए गए
- 20 गोकुल ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं और 41 बुल मदर फार्मों का आधुनिकीकरण किया गया है

आपदा में किसानों की मदद

- आपदा में किसानों को राहत जो पहले न्यूनतम 50 प्रतिशत और उससे अधिक नुकसान होने पर मिलती थी वह अब 33 प्रतिशत और उससे अधिक नुकसान पर मिलेगी
- अति वृष्टि से अनाज को क्षति पहुंचने की स्थिति में पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य अदा किया जाएगा
- मृतक किसानों के परिवारों को सहायता राशि 2.5 लाख से बढ़ा कर 4 लाख रुपये की गई
- एसडीआरएफ संबंधी प्रावधान में 2010-2015 की 5 वर्ष की अवधि की तुलना में 2015-20 की अवधि में 82 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई। यह 33,580 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 61,220 करोड़ रुपये किया गया

एकीकृत कार्यक्रम, ''हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना''

- कृषि क्षेत्र में 11 कार्यक्रमों/मिशनों को एक एकीकृत कार्यक्रम ''हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना'' के अंतर्गत समाहित किया गया

देशभर में 31 मार्च, 2017 तक 24.53 लाख संयुक्त देयता समूहों को बैंकों द्वारा 26,848.13 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए

भाजपा

दुनिया देख रही है एक न्यू इंडिया

भारत ग्लोबल ग्रोथ इंजन बन चुका है

- भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है
- वर्तमान दरों पर 2013 से 2017 के बीच भारतीय GDP में 31% की वृद्धि हुई, जबकि वैश्विक GDP मात्र 4% बढ़ी।
- सभी तरह के इनवेस्टमेंट और मैक्रो-इकोनॉमिक इंडिकेटर में भारत को ऊंचा स्थान मिला है

वैश्विक हुआ योग

- यूएन ने 21 जून, 2015 को पहला योग दिवस मनाया। और तबसे पूरा विश्व 21 जून को बड़े उत्साह के साथ योग दिवस मनाता है
- UNESCO ने मानवता से जुड़े इन्टैन्जबल कल्चर हेरिटेज की लिस्ट में योग को रखा है

क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में भारत का नेतृत्व

- भारत ने COP21 यानि 2015 के पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में अग्रणी भूमिका निभाई थी
- भारत इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी है

पूरी शक्ति के साथ मातृभूमि की रक्षा

- इतिहास में पहली बार भारत ने दिलेरी दिखाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया
- कई दशकों से लंबित वन रेंक, वन पेंशन की मांग को पूरा किया गया है
- डिफेन्स फोर्सेस का ऐतिहासिक आधुनिकीकरण

नए भारत की नई ताकत

- पिछले चार वर्षों में दूसरे देशों से भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।
- दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहली बार विश्व ने भारत की विकास गाथा को सुना।
- भारत ने International Tribunal for the Law of the Sea, International Maritime Organization और Economic and Social Council में अपने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया।
- 2017 में MTCR में शामिल होने के बाद भारत ने Wassenar - Arrangement की सदस्यता हासिल की। 2018 में भारत Australia Group का भी सदस्य बना।

जय विज्ञान

- इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। इनमें अमेरिका के 96 और नीदरलैंड, स्विटजरलैंड, इजरायल, कज़ाख़िस्तान और यूएई के एक-एक उपग्रह शामिल थे।
- IRNSS-1G के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों की सूची में आ गया, जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम NavIC है।
- भारत ने SAARC Satellite लॉन्च किया।

भाजपा

नारी शक्ति, देश की तरक्की

साफ नीयत
सही विकास

महिला शक्ति को नमन करता भारत

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान – मां और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना

- 12,900 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 1.16 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई
- 6 लाख से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई

1,16,00,000
से अधिक गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच

80,00,000
से अधिक गर्भवती महिलाओं को रोगों से बचाव के टीके लगाए गए

50,00,000
से अधिक महिलाओं को प्रतिवर्ष नकदी लाभ पहुंचने की आशा

6,00,000
से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान

बीमारियों से लड़ने के लिए मिशन इंद्रधनुष

- मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को बीमारियों से बचाव के टीके लगाने का अभियान चलाया गया
- 80 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को रोगों से बचाव के टीके लगाए गए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना – गर्भवती माताओं के लिए मदद

- गर्भवती/शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं की मदद के लिए। ऐसी प्रत्येक महिला को 6,000 रुपये की नकद सहायता राशि, जिससे वह समुचित आराम कर सके और समय पर स्वास्थ्य की जांच करा सके
- हर वर्ष 50 लाख से अधिक महिलाओं को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचने की आशा

रोजगार और जीवन के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति अवकाश

- वेतन सहित प्रसूति अवकाश की अवधि बढ़ाकर 26 हफ्ते की गई, जो दुनियाभर में दिए जाने वाले सर्वाधिक प्रसूति अवकाशों में से एक है

पोषण अभियान– समुचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए

- अनेक प्रकार के उपायों के जरिए कुपोषण दूर करने का अपनी तरह का पहला कार्यक्रम
- इसका उद्देश्य तकनीक के इस्तेमाल और लक्ष्य के अनुरूप प्रयास के जरिए कुपोषण में कमी लाना है

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदम

- 104 जिलों में जन्म के समय लड़का-लड़की अनुपात में सुधार
- गर्भ की प्रथम तिमाही के दौरान पंजीकरण में 119 जिलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई
- 146 जिलों में अस्पतालों में प्रसव संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई
- माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिलों में बढ़ोतरी
- बालिकाओं की शिक्षा के लिए अनेक छात्रवृत्तियां

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना – बालिकाओं के लिए सुरक्षित भविष्य

- 1.26 करोड़ से अधिक बालिकाओं के लिए खाते खोले गए, जिनमें करीब 20,000 करोड़ रुपये जमा हुए

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

आज देश में 7.25 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं. 3.6 लाख से अधिक गाँव, 17 राज्य/संघ शाषित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त घोषित हुये हैं

स्वच्छ भारत मिशन से साफ-सफाई के मामले में क्रांति आई

- महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने और खुले में शौच जाने की असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर आदतों को रोकने के लिए देशभर में तेजी से शौचालयों का निर्माण किया गया
- 7.25 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए
- 3.6 लाख से अधिक गांवों और 17 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त किया गया
- स्वच्छता कवरेज जो 2014 में 38 प्रतिशत था, बढ़कर 83 प्रतिशत पर पहुंच गया

मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया- महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन

- मुद्रा योजना के अंतर्गत उद्यमियों को गारंटी रहित ऋण प्रदान किए जाते हैं। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग उद्यमियों को एक करोड़ रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं
- मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना | STAND UP India Endeavour and Prosper

बालिकाओं के प्रति अपराध के मामले में कानून में कड़े प्रावधान

- 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की सज़ा का प्रावधान
- 16 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 20 साल की गई

महिलाओं को धुआं रहित जीवन दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना

- महिलाओं को चूल्हों के धुएं से मुक्ति दिलाने और खाना पकाने में सुविधा पहुंचाने के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3.8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए। इस कार्यक्रम में महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया

महिलाओं को प्राथमिकता

- प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी गयी है
- एकल माताओं को पासपोर्ट नियमों में छूट

महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण

- मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तीन तलाक विधेयक लोकसभा द्वारा पारित
- मुस्लिम महिला बिना किसी पुरुष संरक्षक के अब हज यात्रा कर सकती है

भाजपा

3.8 करोड़ से अधिक महिलाओं को एल.पी.जी गैस कनेक्शन मिले

उज्ज्वला

भाजपा

युवा शक्ति,
देश की तरक्की

साफ नीयत
सही विकास

पढ़ता भारत, आगे बढ़ता भारत

- देश के इतिहास में पहली बार, विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था के सकारात्मक परिणामों तथा शिक्षा क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया
- स्कूली छात्रों में अभिनव कौशल निर्माण के लिए, 2,400 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई। प्रत्येक प्रयोगशाला पर 20 लाख रूपये खर्च आएगा
- 54,000 रैम्पे और रेलिंग बनाई गई और विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए 50,000 विशेष शौचालयों का निर्माण किया गया

उच्च शिक्षा के लिए अवसर बढ़े

- अनेक विश्वविद्यालय, 7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 14 आईआईआईटी, 1 एनआईटी, 103 केन्द्रीय विद्यालय और 62 नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है
- आई.आई.एम. विधेयक पारित कर और गुणवत्ता पूर्ण संस्थानों को ग्रेडिंग कर स्वायत्तता दी गयी जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सुधार है
- 20 संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में घोषित किया जाएगा
- यूजीसी ने 60 शीर्ष विश्वविद्यालयों को ग्रेडिंग कर स्वायत्तता दी
- प्रधानमंत्री रिसर्च फैलोशिप के जरिये प्रतिभावान युवाओं को प्रोत्साहन। 1,000 छात्रों को 5 वर्ष के लिए प्रतिमाह 70,000 से 80,000 रूपये और पी.एच.डी. और अनुसंधान करने के लिए 2 लाख रूपये की वार्षिक सहायता दी जा रही है
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना की गई ताकि पारदर्शी तरीके से अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सभी व्यावसायिक परीक्षाएं कराई जा सकें
- छात्रों की पढ़ाई पूरी कराने के लिए अनेक छात्रवृत्तियां मिलीं
- अध्यापकों के प्रशिक्षण पर विशेष तरीके से ध्यान दिया जा रहा है

03

रोजगार सृजन के लिए तीन स्तरों पर पहल

01 सार्वजनिक क्षेत्र – अधिक अवसर प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का नये सिरे से निर्माण

02 निजी क्षेत्र – एजेंसियों और नौकरी पोर्टलों द्वारा कराए गए अनेक सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं कि युवाओं के लिए अवसर बढ़ रहे हैं

03 व्यक्तिगत क्षेत्र – मुद्रा, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के जरिये

भाजपा

स्टार्ट अप इंडिया के जरिये युवा शक्ति को बढ़ावा

- स्टार्ट अप के लिए सात वर्ष के एक काल खंड में से लगातार तीन वर्ष के लिए करों में छूट
- स्टार्ट अप अब कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे प्रमोटरों के लिए ईएसओपी जारी कर सकते हैं

मुद्रा योजना से उद्यमियों को बल मिला

- अप्रैल 2015 में शुरू होने के बाद से अब तक 12 करोड़ मुद्रा ऋण मंजूर किए गए
- 2018-19 में मुद्रा योजना के लिए बजट बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रूपये किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है

कौशल के साथ भारत, विकास की नई ऊंचाइयों पर

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भारतभर में 13,000 प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए जो 375 व्यवसायों का प्रशिक्षण दे रहे हैं
- पी.एम.के.वी.वाई के अंतर्गत 1 करोड़ युवा प्रशिक्षण लेंगे
- प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों (पी.एम.के.के) के रूप में मशहूर मॉडल प्रशिक्षण केन्द्रों को देश भर के प्रत्येक जिले में स्थापित किया गया है

अनुसंधान और उत्कृष्ठता के लिए अटल नवोन्मष मिशन

- युवाओं के बीच अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए देशभर में इक्यूबेशन सेन्टर और टिंकरिंग प्रयोगशालाएं बन रही हैं
- उच्चकोटि के शिक्षकों, परामर्शदाताओं, उद्यमियों और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को एक जगह पर लाकर युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है

राष्ट्रीय युवा मार्गदर्शक कार्यक्रम

- दिसम्बर 2014 में राष्ट्रीय युवा मार्गदर्शक कार्यक्रम की शुरूआत। जिससे युवाओं को सम्मिलित कर नीतियां बनाई जाएं, युवाओं को विकास की प्रक्रिया का अभिन्नय हिस्सा बनाया जाए और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हो

खेलों और खेल की भावना को आगे बढ़ाना

'खेलो इंडिया'

- खेलों की संस्कृति और युवाओं में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन
- विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता वाले खेलों में पहचाने गए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये की वार्षिक वित्तीय सहायता
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 31 जनवरी 2018 को पहले खेलो इंडिया स्कूल खेलों की शुरूआत की। 29 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों के 3507 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया
- नये खेलो इंडिया कार्यक्रम का बजट 2017-18 से 2019-20 के लिए 1,756 करोड़ रूपये होगा

खेल प्रतिभा खोज पोर्टल की शुरूआत

- यह पोर्टल प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी उपलब्धियां बांटने का मंच प्रदान करता है। यह उभरते खिलाड़ियों को भी बढ़ावा देता है

मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय

- मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, खेल टेक्नोलॉजी, खेल प्रबंधन, खेल कोचिंग के क्षेत्रों में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है और चुने हुए प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा

पैरा एथलीटों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र:

- गुजरात के गांधीनगर में 5 फरवरी, 2017 को पैरा एथलीटों को समर्पित विश्वस्तर की सुविधाओं के साथ पहला प्रशिक्षण केन्द्र

ऐतिहासिक राष्ट्रमंडल खेल 2018 की पदक तालिका:

- ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा और भारतीय खिलाड़ियों ने 66 पदक जीते

गुजरात के गांधीनगर में 5 फरवरी, 2017 को पैरा एथलीटों को समर्पित विश्वस्तर की सुविधाओं के साथ पहला प्रशिक्षण केन्द्र

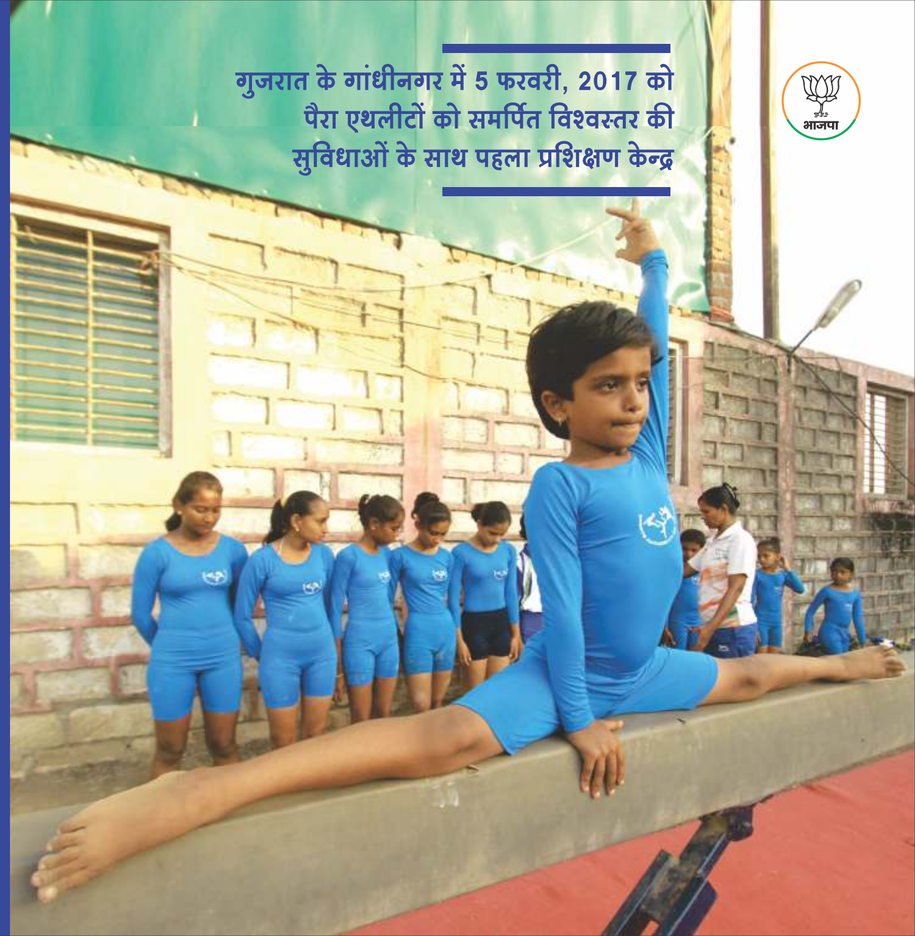

भाजपा

स्वस्थ भारत –
स्वस्थ और समर्थ बनता भारत

साफ नीयत
सही विकास

आयुष्मान भारत

आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा पहल

Rs. 5,00,000

इससे करीब 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का विस्तृत स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा

1,50,000 उप-केन्द्र

विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.5 लाख उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) में परिवर्तित किया जा रहा है

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से गर्भवती माताओं के लिए सहायता

- गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, ताकि वे आराम कर सकें और समय पर स्वास्थ्य जांच करा सकें
- हर वर्ष 50 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद

मां और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

- 12,900 स्वास्थ्य केन्द्रों में 1.16 करोड़ से अधिक प्रसव पूर्व जांच की गई
- उच्च जोखिम वाली 6 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

पोषण अभियान - सही पोषण के लिए।

- बहुविध चिकित्सा सुधार के जरिए कुपोषण से निपटने के लिए पहली बार अपनी तरह की पहल
- एकीकृत, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और लक्षित दृष्टिकोण के जरिए कुपोषण को कम करने का लक्ष्य

भाजपा

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की गई

- जीवन रक्षक दवाओं सहित 1,054 आवश्यक औषधियों को मई 2014 के बाद मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया। जिससे उपभोक्ताओं को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का फायदा मिला
- स्टेंट और नी इम्प्लांट केप की कीमतों में 50-70 प्रतिशत की कमी की गई जिससे आम आदमी की काफी बचत हुई
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्रों में दवाओं की बिक्री से देशभर में जनेरिक दवाएं सस्ती हो गईं। 3,000 से ज्यादा स्टोर काम कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप आम आदमी की 50 प्रतिशत से अधिक बचत हो रही है
- अमृत फार्मेसियां कैंसर और कार्डियोवैस्क्यूलर (हृदयवाहिनी) बीमारियों की दवाओं के साथ-साथ कार्डिएक इम्प्लांट की दवाएं वर्तमान बाजार दरों के मुकाबले 60 से 90 प्रतिशत की रियायत पर बेच रही हैं
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबों के लिए डायलिसिस सेवाएं और सभी मरीजों के लिए रियायती दरों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 497 डायलिसिस इकाइयों को परिचालन योग्य बनाया गया है, करीब 2.5 लाख मरीज इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं और अब तक 25 लाख डायलिसिस सत्र हो चुके हैं

टीकाकरण - बीमारियों की रोकथाम

- मिशन इंद्रधनुष के चार चरण पूरे हो चुके हैं जिसमें 528 जिलों को शामिल किया गया है। जहां:
  - 3.15 करोड़ बच्चों को टीके लगाए जा चुके हैं
  - 80.63 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है
- भारत ने मातृत्व और नवजात शिशुओं में टिटनस समाप्त करने की मई 2015 में पुष्टि कर दी है, यह कार्य विश्व बैंक द्वारा निर्धारित दिसम्बर 2015 के लक्ष्य से पहले पूरा कर लिया गया है
- पोलियो वायरस को रोकने संबंधी टीका (आई.पी.वी) की शुरूआत नवम्बर 2015 में की गई और देशभर में बच्चों को आई.पी.वी की करीब 4 करोड़ ख़ुराक दी जा चुकी है
- रोटा वायरस टीके की शुरूआत मार्च 2016 में हुई और रोटा वायरस टीके की करीब 1.5 ख़ुराक बच्चों को दी जा चुकी है
- ख़सरा रूबैला (एमआर) टीकाकरण अभियान की शुरूआत फरवरी 2017 में हुई और 8 करोड़ बच्चों को ये टीके लगाए जा चुके हैं
- न्यूमोकोकल कज्यूकेट वैक्सीन (पीसीवी) की शुरूआत मई 2017 में हुई और पीसीवी की करीब 15 लाख से अधिक ख़ुराक बच्चों को दी जा चुकी हैं
- संचारी रोगों की रोकथाम - कुष्ठ रोग 2018 तक, ख़सरा 2020 तक और तपेदिक 2025 तक समाप्त करने की कार्य योजना लागू की गई है

स्वस्थ भारत के लिए नीतियां

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 15 वर्ष के अंतराल के बाद 2017 में बनाई गई ताकि बदलते सामाजिक-आर्थिक और महामारी विज्ञान संबंधी परिदृश्य में वर्तमान और उभरती चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके
- मानसिक स्वास्थ्य सेवा कानून में भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए अधिकारों पर आधारित वैधानिक ढांचा अपनाया गया है। यह मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का सामना कर रहे लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधानों में समानता और निष्पक्षता की भावना को मजबूत बनाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी अधिकतम देखभाल हो और वे प्रतिष्ठित और सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें

अधिक बिस्तर, अधिक सुविधाएं, अधिक अस्पताल और अधिक डॉक्टर

- 20 नये एम्स, जैसे नये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं
- जुलाई 2014 से, काम कर रहे छह एम्स में 1675 अतिरिक्त बिस्तर लगाए गए हैं (पिछले एक वर्ष में शामिल 850 बिस्तरों सहित)
- वर्ष 2017-18 में झारखंड और गुजरात के लिए 2 नये एम्स की घोषणा
- 73 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन किया जा रहा है
- पिछले चार वर्षों में कुल 92 मेडिकल कॉलेज (46 सरकारी और 46 निजी) स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे 15,354 एम.बी.बी.एस सीटें बढ़ी हैं
- पिछले चार वर्षों में 12,646 पी.जी सीटें बढ़ी हैं

वैश्विक लक्ष्य से पहले तपेदिक (टीबी) का सफाया

- दवा बेअसर तपेदिक का इलाज 4,00,000 से अधिक डी.ओ.टी केन्द्रों के एक नेटवर्क के जरिये किया जा रहा है
- 5.5 करोड़ की आबादी के घर-घर जाकर तपेदिक के लक्षणों की स्क्रिनिंग की गयी
- डी.बी.टी के जरिये तपेदिक के इलाज की अवधि के दौरान सभी टी.बी मरीजों को पोषण सम्बन्धी सहायता- प्रति माह 500 रूपये

समग्र स्वास्थ्य सेवा के लिए योग

- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 से हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। वर्षभर योग में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी से स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभ मिले हैं

एच.आई.वी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) कानून, 2017

- इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों के अनुसार 2030 तक इस संक्रामक रोग को समाप्त करना है

अंतराष्ट्रीय योग दिवस 2015 से हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। वर्ष भर योग में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी से स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभ मिले हैं।

भाजपा

सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध सरकार

साफ नीयत
सही विकास

7,565 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरण से 2014-15 और 2015-16 के दौरान 3.3 करोड़ से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित

शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण

- 7,565 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरण से 2014-15 और 2015-16 के दौरान 3.3 करोड़ से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित
- ओ.बी.सी. के लिए मेट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति आय पात्रता 44,500 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष की गयी
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के लिए आय पात्रता दो लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की गई
- घर से पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों के लिए स्टाइपेंड 150 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों का स्टाइपेंड 350 से बढ़ाकर 525 रुपये किया गया
- अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के नि:शुल्क कोचिंग की आय पात्रता 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई।
- स्थानीय विद्यार्थियों के लिए स्टाइपेंड 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये तथा दूसरे स्थानों के विद्यार्थियों के लिए स्टाइपेंड 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया
- अन्य पिछड़े वर्गों की मेट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति की दरों में काफी वृद्धि की गई

अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए

95,000 करोड़ रुपये

का ऐतिहासिक बजट

41%

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए बजट आवंटन में

41 प्रतिशत की वृद्धि

बढे संसाधन, पूरी हुई आकांक्षाएं

- अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए 95,000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट
- 2017-18 की तुलना में 2018-19 में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए बजट आवंटन में 41 प्रतिशत की वृद्धि

Accessible India Campaign

Accessible India • Empowered India

सुगम्य भारत- बेहतर भारत

- 3 दिसंबर, 2015 को शुरूकिए गए सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य दिव्यांग बहनों और भाइयों को सुगम्य और सम्मान जीवन प्रदान करना है
- देश की राजधानी और सभी राज्यों की राजधानियों के कम से कम 50 प्रतिशत सरकारी भवनों को पूरी तरह सुगम्य बनाने के लिए तेजी से प्रयास जारी
- 8 लाख दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरित करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन
- 50 शहरों में 1662 महत्वपूर्ण भवनों की सुगम्यता की जांच अब तक पूरी
- सभी 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा सभी 48 घरेलू हवाई अड्डों में रैम्प, सुगम्य शौचालय, लिफ्ट में ब्रेल लिपि में संकेतक तथा सुनने योग्य संकेतकों जैसी सुगम्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं
- 709 ए1, ए, बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों में से 644 रेलवे स्टेशन तथा 1,41,572 बसों अड्डों में से 12894 बसों अड्डों को सुगम्य बनाया गया है
- राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों की 917 चिन्हित वेबसाइटें ईआरएनईटी इंडिया के माध्यम से सुगम्य बनाए जाने की प्रक्रिया में हैं

मई 2014 से पूरे देश में आयोजित 5,790 शिविरों से 6 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं

दिव्यांग सारथी
Divyang Sarathi

दिव्यांग भाइयों और बहनों को मिले अधिक अवसर

- सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया। इसका सकारात्मक प्रभाव होगा
- दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए शिविरों के आयोजन में अप्रत्याशित वृद्धि। मई 2014 से पूरे देश में आयोजित 5790 शिविरों से 6 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं

शिक्षित भारत, सक्षम भारत

- दिव्यांग विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से 11 नवंबर, 2014 को छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई
- 30 हजार रुपये की छात्रवृत्ति राशि ट्यूशन फीस भुगतान के लिए और 20 हजार रुपये की राशि आकस्मिक भत्ते के रूप में दी गई, योजना के तहत प्रतिवर्ष 1,000 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी
- इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (आई.एस.एल.आर.टी.सी) स्थापित

क्योंकि हम ख्याल रखते हैं

- निरामय योजनाः ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी तथा अनेक दिव्यांगताओं के शिकार लोगों को एक लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवच

मुद्रा - 125 करोड़ भारतीयों में विश्वासः

- 2018 के बजट में मुद्रा के अंतर्गत ऋण लक्ष्य, 2018-19 वित्त-वर्ष के लिए बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये किया गया
- कुल ऋण खातों में से 76 प्रतिशत ऋण खाते महिलाओं के हैं और 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं

संसाधनों की सीमा नहीं

- उद्यम पूंजी कोष योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए 63 कंपनियों को 239.12 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। (4 मई, 2018 तक)
- अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष की तर्ज पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी कोष की नई योजना 200 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ शुरूकी जाएगी। इसके लिए 2018-19 में 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

स्टैंड अप इंडिया - आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

- बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति, महिला कर्जदारों को फरवरी, 2018 तक 54,733 ऋण स्वीकृत

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना | STAND UP India Endeavour and Prosper

सामाजिक आधिकारिता के लिए तैयारी - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016

- दिव्यांगता के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 कर दिए गए हैं
- बोलने और भाषा की दिव्यांगता और विशेष रूप से सीखने की दिव्यांगता को पहली बार शामिल किया गया है
- तेजाब हमले के पीड़ितों को भी शामिल किया गया है
- 6 से 18 वर्ष की आयु-वर्ग में दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार तथा सरकारी और सरकारी सहायता से चलने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 4 प्रतिशत का आरक्षण
- दिव्यांगजनों के साथ होने वाले अपराधों के लिए दंड

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में संशोधन कर मजबूत किए अधिकार

- संशोधन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध होने वाले अत्याचार के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान
- पीड़ितों और गवाहों से संबंधित नया अध्याय जोड़ा गया
- पीड़ितों, प्रतिवादियों और गवाहों की रक्षा के प्रबंध करने के लिए राज्यों को कुछ निश्चित कर्तव्य और दायित्व सौंपना

क्योंकि वे थे, हम हैं

- भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जन-जातीय समुदायों के शौर्य और वीरता की स्मृति में जनजातीय बहुल जिलों में अत्याधुनिक जन-जातीय संग्रहालय

नई पीढ़ी को डॉ. बाबा साहब आंबेडकर से जोड़ना

- दिसंबर, 2017 में 15 जनपथ पर डॉ. अम्बेडकर अंतराष्ट्रीय केन्द्र खोला गया। इस विश्वस्तरीय भवन की आधारशिला भी अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रखी गई
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 13 अप्रैल, 2018 को 26 अलीपुर रोड पर महापरिनिर्वाण भूमि स्थल का उद्घाटन। वास्तुकला से सुसज्जित इस भवन में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन और उनके कार्यों को प्रदर्शित किया गया है

भाजपा

बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति, महिला कर्जदारों को फरवरी, 2018 तक 54,733 ऋण स्वीकृत

भाजपा

हर एक का विकास,
हर एक के लिए बेहतर जीवन

साफ नीयत
सही विकास

सौभाग्य
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

बेहतर जीवन स्तर: गरीबों के सपनों को लगे पंख

करोडों लोगों की आकांक्षाओं को मिला बल

- देश के किसी भी गांव में अब अंधेरा नहीं है। डी.डी.यू.जी.जे.वाई ने प्रत्येक गांव में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की
- 'सौभाग्य' योजना के जरिये हर घर में बिजली पहुंचाई जा रही है। योजना के तहत 4 करोड़ गैर-विद्युतीकृत घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य

Atal Pension Yojana

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

वित्तीय समावेश- नई आकांक्षाएं

'जन-धन' के जरिए बैंकिंग सुविधाओं से वंचित गरीब लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करना

- 31.52 करोड़ जन-धन खाते खोले गए
- इंडिया पोस्टल पेमेंट्स बैंक के माध्यम से गरीबों और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों के दरवाजे तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाए जाने की व्यवस्था

गरीबों के लिए बीमा योजना 'जन सुरक्षा': आवश्यकता के समय मदद

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रतिवर्ष 12 रुपये के प्रीमियम पर व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के साथ 13.25 करोड़ लोगों का बीमा
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रतिवर्ष 330 रुपये के प्रीमियम पर जीवन बीमा कवर से 5.22 करोड़ परिवार लाभान्वित
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली अटल पेंशन योजना के सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गयी है
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को कल्याण और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को उनके जमा धनराशि पर 10 वर्षों तक 8 प्रतिशत की सुनिश्चित ब्याज दर दी जा रही है। निवेश की सीमा दोगुनी कर 15 लाख रुपये कर दी गई है और इस योजना की अवधि वर्ष 2020 तक बढ़ा दी गई है

उज्ज्वला योजना से करोड़ों गरीब परिवारों के लिए धुआं-रहित जीवन सुनिश्चित किया गया

- 3.8 करोड़ गरीब महिलाओं को एल.पी.जी कनेक्शन दिए गए
- 8 करोड़ महिलाओं को एल.पी.जी कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य

3.8 करोड़ गरीब महिलाओं को एल.पी.जी कनेक्शन दिए गए। 8 करोड़ महिलाओं को एल.पी.जी कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य

भाजपा

7.25 करोड़ से भी अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया,
3.6 लाख से भी ज्यादा गांव और 17 से भी अधिक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश ओ.डी.एफ (खुले में शौच से मुक्त) घोषित किए गए

स्वच्छता कवरेज वर्ष 2014 के
38 प्रतिशत से बढ़कर 83 प्रतिशत
के स्तर पर पहुंची

शौचालयों के त्वरित निर्माण से देश की करोड़ों
महिलाओं को मिला सम्मान
और खुले में शौच जैसी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आदत से मिली मुक्ति

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

80 करोड़ से भी अधिक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा

- मई, 2014 के सिर्फ 11 राज्यों की तुलना में अब समस्त 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है

मनरेगा के जरिए ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण रोजगार

- 85 प्रतिशत मामलों में 15 दिनों के अंदर ही संबंधित कामगारों को पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया, जबकि विगत में इस तरह के भुगतान में काफी देरी होती थी
- इसकी शुरुआत से लेकर अब तक महिलाओं की भागीदारी बढ़कर वर्ष 2016-17 में 56 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई

शोषण की समाप्ति: सशक्तिकरण सुनिश्चित

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से अब सीधे खाते में पैसा, बिचौलियों से छुटकारा

- पिछले 4 वर्षों में 431 योजनाओं के तहत 3,65,996 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई
- पहल - यह विश्व का सबसे बड़ा नकदी हस्तांतरण कार्यक्रम है, जिसके तहत 20.14 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को 69,815 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि प्राप्त हुई

प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए वर्ष 2022 तक सभी को घर

- शहरी क्षेत्रों में 1.2 करोड़ से भी अधिक किफायती मकानों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ से भी अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से प्रत्येक गांव को जोड़ने की मुहिम

- ग्रामीण सड़कों की पहुंच वर्ष 2014 के 56 प्रतिशत से बढ़कर 82 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है
- पिछले 4 वर्षों में लगभग 1.69 लाख किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया

श्रम कल्याण के लिए श्रमेव जयते

- न्यूनतम पारिश्रमिक में 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 55 लाख कामगार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए
- सातवें वेतन आयोग से 50 लाख कर्मचारी और 35 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए
- ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टर) जैसे कि वस्त्र, चमड़ा और फुटवियर में सरकार द्वारा 3 वर्षों तक नए कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में 12 प्रतिशत का योगदान करना
- 1 जनवरी, 2016 से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। यह निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी लागू है
- प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया। स्टाइपेंड (वजीफा) को न्यूनतम पारिश्रमिक से जोड़ा गया
- पारिश्रमिक भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2017: नियोक्ता इसके तहत कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान या तो नकद करेंगे या चेक के जरिए करेंगे अथवा कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर देंगे
- कामगारों को स्थायी पहचान प्रदान करने के लिए अनूठी कामगार पहचान संख्या (यू.आई.एन) आवंटित

मिशन अंत्योदय

- बजट 2017-18 में इसकी घोषणा की गई। इसका लक्ष्य मापनीय परिणामों के आधार पर 50,000 ग्राम पंचायतों के 1 करोड़ परिवारों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना है

भाजपा

नए भारत के लिए नया बुनियादी ढांचा

साफ नीयत
सही विकास

घर हो अपना, सबका सपना – प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई)

- आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2022 में सभी के पास अपना घर हो
- पहले ब्याज दर पर 6.5 प्रतिशत की छूट के साथ 6 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाते थे, अब 9 लाख रुपये और 12 लाख रुपये के आवास ऋण ब्याज दर पर क्रमश: 4 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की छूट के साथ दिए जाते है
- पिछले साढ़े तीन वर्षों में, शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीब 1 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया

स्मार्ट सिटी – बेहतर सिटी

- बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन और क्षेत्र आधारित विकास, निरंतर शहरी नियोजन और विकास सुनिश्चित करने के लिए करीब 100 शहरी केन्द्रों का स्मार्ट सिटी के रूप में चयन
- इन शहरों में विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं पर 2,01,979 करोड़ रुपये खर्च आएगा और इसका करीब 10 दस करोड़ भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

गांव मजबूत बने – श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन के साथ

- अगले 3 वर्षों के दौरान ऐसे 300 रुर्बन क्लस्टरों का विकास जो खुले में शौच मुक्त हरे-भरे हों और साथ ही कृषि आधारित और कौशल श्रम बल पर आधारित विषय क्षेत्र संबंधी क्लस्टर हों तथा आर्थिक अवसरों तक उनकी पहुंच हो
- 267 क्लस्टरों की पहचान हो चुकी है. 29 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के लिए 153 समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं को मंजूरी जो प्रत्येक क्लस्टर में निवेश की मूल योजना है

गांव जुड़े सड़कों से- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- 2019 तक हर गांव को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना। ग्रामीण सड़क संपर्क 2014 में जो 56 प्रतिशत था अब बढ़कर 82 प्रतिशत हो चुका है, इसमें सुदूरवर्ती और दुर्गम इलाकों के गांव भी शामिल हैं।
- निकट भविष्य में 73,727 किलोमीटर सड़कों का निर्माण का लक्ष्य

व्यापक परिवर्तन के लिए अधिक सड़कें और राजमार्ग बने

- सड़क निर्माण पर व्यय 2013-14 में 32,483 करोड़ रुपये की तुलना में 2017-18 में 1,16,324 करोड़ रुपये किया गया
- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का वर्ष 2013-14 के 92,851 किलोमीटर की तुलना में 2017-18 में 1,20,543 किलोमीटर विस्तार हुआ
- निर्माण की गति 2013-14 के 12 किलोमीटर प्रतिदिन के मुकाबले बढ़कर 2017-18 में 27 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है
- निर्माण और विकास के लिए 2,000 किलोमीटर तटीय सम्पर्क सड़कों की पहचान की गई
- भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग - चेनानी - नाशरी सुरंग जनता के लिए खोली गई
- भारत का सबसे लम्बा पुल - असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 9.15 किलोमीटर लम्बा ढोला - सादिया पुल 26 मई, 2017 को आम जनता को समर्पित। इस पुल ने ऊपरी असम एवं अरूणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से के बीच 24 घंटे संपर्क सुनिश्चित किया है
- भरूच में नर्मदा एवं कोटा में चम्बल नदी पर बने पुल आम जनता के लिए खोल दिए गए
- उच्च सघनता वाले गलियारे में 1,000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे

भारतमाला परियोजना: प्रथम चरण

- मल्टी मॉडल समेकन के साथ राजमार्ग क्षेत्र के विकास के लिए 5,35,000 करोड़ रुपये का नया कार्यक्रम

सुरक्षित सड़कों के लिए सेतु भारतम परियोजना

- रेलवे ओवर ब्रिज/अंडर पासों के निर्माण से 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त कर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना
- 20,800 करोड़ रुपये की धनराशि से रेलवे ओवर-ब्रिजों/अंडर-ब्रिजों का निर्माण करना

सुरक्षित और स्मरणीय तीर्थयात्रा होगी – चारधाम महामार्ग विकास परियोजना से

- 2016 से आरम्भ परियोजना का उद्देश्य हिमालय में चारधाम तीर्थयात्रा केन्द्रों के लिए संपर्क में सुधार लाना और इन केन्द्रों तक यात्रा को अधिक सुरक्षित, त्वरित एवं सुविधाजनक बनाना
- 12,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लगभग 900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास कार्य प्रगति पर

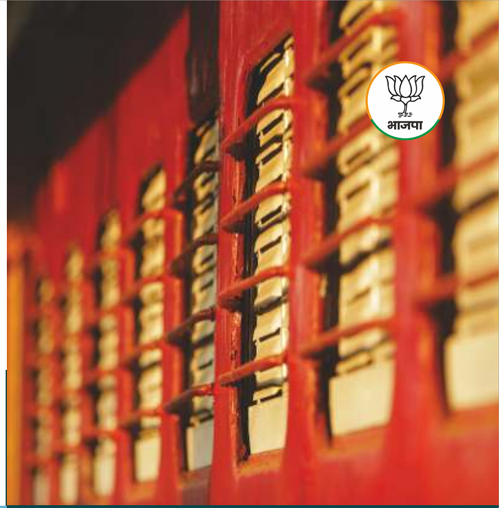

रेलवे

क्योंकि हम चिंता करते हैं – हमारी प्राथमिकता – सुरक्षा पहले

- 2017-18 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड: एक वर्ष में 100 से कम दुर्घटनाएं दर्ज हुईं। अनुवर्ती रेल दुर्घटनाओं में 62 प्रतिशत की कमी, जो 2013-14 के 118 से घटकर 2017-18 में 73 पर आ गई
- पिछले चार वर्षों के दौरान 5,469 मानवरहित क्रॉसिंग समाप्त किए गए। हटाने/समाप्त करने की औसत गति 2009-14 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक रही
- ब्रॉड गेज पर सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को 2020 तक समाप्त करने का लक्ष्य

चौतरफा और विस्तृत विकास

- पूर्वोत्तर के लिए सम्पर्क
  - समूची छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र शेष भारत से पूरी तरह जुड़ गया है
  - पहली बार मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के रेल नक्शे पर आ गए
- मुंबई-अहमदाबाद उच्च गति की रेल: भारत की पहली बुलेट ट्रेन
  - तेज गति वाली इस ट्रेन से यात्रा का समय 8 घंटे से कम होकर 2 घंटे हो जाएगा
  - निर्माण के दौरान लगभग 20,000 श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर

अधिक माल ढुलाई से मजबूत हुई अर्थव्यवस्था

- 2017-18 में सबसे अधिक माल ढुलाई की गई: 1,160 मिलियन टन

उड़ान योजना के जरिए अब सभी हवाई यात्रा कर सकते हैं

- अपर्याप्त हवाई सेवाओं वाले क्षेत्रों में हवाई अड्डों के लिए उड़ान योजना 2,500 रुपये प्रति घंटे के वित्तीय छूट किराये पर रीजनल एयर कनेक्टिविटी प्रदान करती है

नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उछाल

- भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में उभरा है। पिछले तीन वर्षों में यात्रियों की संख्या में 18-20 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई
- भारत में पहली बार हवाई यात्रा करने वालों की संख्या वातानुकूलित ट्रेन यात्रा करने वालों से ज्यादा हुई। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 100 मिलियन के पार पहुंची
- आजादी के बाद केवल 75 हवाई अड्डे शुरू हुए जबकि उडान के तहत दिसम्बर 2016 से अब तक 25 हवाई अड्डे जोड़े गए
- आधुनितम बुनियादी ढांचा बनाकर हम नए भारत की नींव रख रहे हैं
- इस क्षेत्र की कायापलट के लिए राष्ट्रीय विमानन नीति-2016 की शुरूआत

100 मिलियन
2017 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या

18-20%
पिछले तीन सालों में हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि

2,500 रूपये प्रति घंटे
उडान योजना के तहत किराया

राष्ट्र निर्माण के लिए जल शक्ति

सागरमाला परियोजना

- 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बुनियादी ढांचा निवेश के साथ 500 से अधिक परियोजनाएं शामिल

बंदरगाह संचालित विकास की ओर

- अप्रैल से दिसम्बर, 2017 के दौरान प्रमुख बंदरगाहों के कार्यक्षमता मानदंड चिह्नित। जहाज से माल उतारने और लादने का कार्य 73 घंटे की तुलना में 65 घंटे में सम्पन्न
- प्रमुख बंदरगाहों के ऑपरेटिंग सरप्लस में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि

भाजपा

8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बुनियादी ढांचा निवेश के साथ 500 से अधिक परियोजनाएं शामिल

भाजपा

तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था

साफ नीयत
सही विकास

भारत वैश्विक ग्रोथ इंजन बना

- अर्थव्यवस्था का मजबूती से आगे बढ़ना जारी रहेगा, वित्त-वर्ष 2018-19 में 7.4 प्रतिशत की दर से जी.डी.पी बढ़ने का अनुमान
- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 418.94 बिलियन अमरीकी डॉलर हुआ
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2013-14 के 36.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2016-17 में 60.08 बिलियन डॉलर हुआ
- मुद्रास्फीति अप्रैल 2014 के 8.48 प्रतिशत से घटकर अप्रैल 2018 में 4.58 प्रतिशत हुई, खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल 2014 के 9.19 प्रतिशत से घटकर अप्रैल 2018 में 3.07 प्रतिशत हुई
- भारत का सकल घरेलू उत्पादन वर्तमान मूल्यों में 2013 से 2017 के बीच 31 प्रतिशत बढ़ा, जबकि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई
- विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत का हिस्सा 2013 के 2.43 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 3.08 प्रतिशत हो गया। विश्व सकल घरेलू उत्पाद में भारत का हिस्सा 2005 के 1.75 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 2.43 प्रतिशत हुआ था। इस तरह वैश्विक वृद्धि में जो योगदान 4 वर्षों में हासिल किया गया, पहले 8 वर्ष उसके लिए लगे थे

जी.एस.टी से कारोबार आसान हुआ

- अनेक करों और खंडित कर व्यवस्थाओं की समाप्ति से छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को लाभ मिला
- करों के दुष्प्रभाव में कमी
- कीमतों में गिरावट
- चेक पोस्टों की समाप्ति से पूरे देश में परिवहन में लगने वाले समय में महत्वपूर्ण कमी

आर्थिक क्षेत्र में साहसिक सुधार, मजबूत होते संस्थान और आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था

- वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्र को अनुमति
- रियल एस्टेट नियमन अधिनियम (रेरा) से मकान खरीदने वालों के सपने, अधिकारों और निवेश की सुरक्षा
- 72,500 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य पार किया
- पारदर्शी संसाधन आवंटन के साथ 89 कोयला खानों का आवंटन

बैंकिंग सुधारों से अर्थव्यवस्था को बल मिला

- ऐतिहासिक दिवाला और दिवालियापन संहिता के महत्वपूर्ण परिणाम
- जमापूंजी में वृद्धि और रोजगार सृजन को समर्थन देने के लिए अगले दो वर्षों में 2,11,000 करोड़ रुपये लगाने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पुंजीकरण
- बैंकों को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की स्वीकृति

अनुपालन में सरलता के जरिए श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करना

- कर्मचारियों को ई.पी.एफ.ओ खातों के हस्तांतरण में अब कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। सार्वभौमिक खाता संख्या (यू.ए.एन) से पोर्टेबिलिटी को बढ़ावा मिला है

भाजपा

श्रम सुविधा पोर्टल: अनूठी कामगार पहचान संख्या आवंटित, प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन पंजीकरण।

- पारिश्रमिक भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2017: नियोक्ता इसके तहत कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान या तो नकद करेंगे या चेक के जरिए करेंगे अथवा कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर देंगे

देश के विकास इंजनों 'एम.एस.एम.ई' को नई मजबूती प्रदान करना

- गारंटी (जमानत) के बिना ऋण, 12 करोड़ छोटे उद्यमियों के असीमित सपने 'मुद्रा' योजना से लाभान्वित हुए
- 50 करोड़ रुपये के बजाय अब 250 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है

आयकर जमा करने वालों की संख्या बढ़ी

- वित्त-वर्ष 2017-18 में 6.84 करोड़ आई.टी.आर दाखिल किए गए, जो वित्तवर्ष 2013-14 की तुलना में 80.5 प्रतिशत अधिक है

12 करोड़ छोटे उद्यमियों के असीमित सपने 'मुद्रा' से लाभान्वित हुए

'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में भारत की रैंकिंग वर्ष 2014 के 142 वें पायदान से 42 स्थान सुधर कर वर्ष 2018 में 100 वें पायदान पर पहुंच गई

डब्ल्यू.ई.एफ के 'वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक' में भारत की रैंकिंग वर्ष 2014-15 के 71 वें पायदान से सुधर कर वर्ष 2016-17 में 39 वें पायदान पर पहुंच गई

INDIA 2 1 3

भारत ग्रीनफील्ड एफडीआई आकर्षित करने की दृष्टि से दुनिया में नंबर वन है

3RD

भारत अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट (डब्ल्यूआईआर) में वर्ष 2016-18 के लिए शीर्ष संभावित मेजबान अर्थव्यवस्थाओं की सूची में तीसरे पायदान पर है

TOP 10

भारत वर्ष 2016 के दौरान देश में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) प्रवाह सूची में 9वें पायदान पर रहा - विश्व निवेश रिपोर्ट 2017

मूडीज ने 14 वर्षों में पहली बार भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'बीएए3' से बढ़ाकर 'बीएए2' कर दिया

भारत मोबाइल फोन बनाने वाला हब बना

- 120 मोबाइल विनिर्माण इकाईयां स्थापित की गईं, जबकि वर्ष 2014 में केवल 2 इकाईयां ही स्थापित की गई थीं
- वर्ष 2014-15 में बनें 6 करोड़ मोबाइल हैंडसेटों की तुलना में वर्ष 2017-18 में 22.5 करोड़ मोबाइल हैंडसेट बनाए गए
- वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में 1.32 लाख करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल हैंडसेट बनाए गए

भाजपा

2013 से 2017 के बीच
भारत का जी.डी.पी.
31%
बढ़ा जबकि ग्लोबल जी.डी.पी.
4%
जितना बढ़ा

भाजपा

भ्रष्टाचार पर वार, ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था

साफ नीयत
सही विकास

भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई

01 मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में विशेष जांच दल का गठन

02 विमुद्रीकरण के कारण भारत में अब तक के सबसे बड़े संदेहास्पद लेनदेन और जमाधन का पता चला। हमारी अर्थव्यवस्था में अब उच्च मूल्य नोटों की मौजूदगी विमुद्रीकरण के पूर्व के मुकाबले काफी कम है

03 मॉरिशस, साइप्रस, सिंगापुर के साथ दोहरे कराधान से बचाव का करार

04 स्विट्ज़रलैण्ड के साथ अद्यतन सूचना साझा करने का समझौता

05 कालाधन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) तथा कर अधिरोपण क़ानून, 2015 लागू

06 धनशोधन निवारण अधिनियम में संशोधन: विदेश में जमा काले धन के बराबर संपत्ति को जब्त करने की मिली अनुमति

07 बेनामी संपत्ति अधिनियम के ज़रिये कालेधन पर कसी लगाम

08 करीब तीन लाख फर्ज़ी कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही

09 आर्थिक भगोड़ों की सम्पत्तियों को ज़ब्त करने के लिये भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक पेश। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर लगाम कसने और धन वसूल करने में सहायता मिलेगी

सुचारू अर्थव्यवस्था का बढा दायरा, लोगों के अधिकार हुए सुरक्षित

2017-18 के दौरान भरे गये आयकर रिटर्न की संख्या बढ़कर 6.84 करोड़ हुई। जो 2013-14 की तुलना में 80.5% अधिक है

50 लाख नये बैंक खाते खोले गए, जिससे कर्मचारियों का वेतन पारदर्शी तरीके से सीधे उनके खाते में पहुंचा

1 करोड़ से अधिक करदाता जीएसटी में पंजीकृत हुए। इससे पहले पंजीकृत करदाताओं की संख्या 65 लाख थी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 1.01 करोड़ से अधिक कर्मचारियों का नामांकन हुआ। विमुद्रीकरण के बाद 1.3 करोड़ से अधिक कर्मचारी ई.एस.आई.सी के साथ पंजीकृत हुए

पारदर्शी सरकार-पक्षपात रहित फैसले

- कोल ब्लॉक एवं टेलीकोम स्पैक्ट्रम के पारदर्शी आवंटन ने एक नया मानदण्ड स्थापित किया
- अराजपत्रित पदों के लिये इंटरव्यू को खत्म करने से सुयोग्य उम्मीदवार चुने गए, पक्षपात और भ्रष्टाचार दूर हुआ
- परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी में लगने वाला समय 600 दिन से घटकर 180 दिन हुआ। सभी प्रकार के अनुमोदन के लिये ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य हुआ

तकनीक का इस्तेमाल - पारदर्शिता बढ़ी

- पिछले चार वर्ष में 431 योजनाओं के लाभान्वितों के बैंक खातों में 3,65,996 करोड़ रुपये से अधिक भेजे गए
- सरकारी खरीद अब जी.ई.एम. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही संभव। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और पादर्शिता बढ़ेगी
- आधार को वैधानिक ढांचा मिला
- 1 करोड़ से अधिक आयकर दाताओं ने अपने आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ा

राजनैतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए प्रावधान

- राजनैतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिये प्रति व्यक्ति नकद दान की सीमा 2,000 रुपये की गई
- चुनावी बांड जारी करने से कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगेगी

विमुद्रीकरण के बाद 1.3 करोड़ से अधिक कर्मचारी ई.एस.आई.सी के साथ पंजीकृत हुए

भाजपा

नई गति और नए आयाम के साथ आगे बढ़ता भारत

साफ नीयत
सही विकास

गरीबों के अपने आवास के सपने को तेजी से साकार करना

- पिछले 4 वर्षों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ आवास बनाए गए

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) में रिकॉर्ड गति से ग्रामीण सड़कों का निर्माण

- ग्रामीण सड़क संपर्क बढ़कर 82% गांवों तक पहुंचा, जो 2014 में 56% गांवों तक था
- 2013-14 में औसतन 69 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण होता था, जो 2017-18 में 134 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया

स्मार्ट सिटी मिशन

- 100 शहरों में क्षेत्र आधारित विकास के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचागत बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना

एक्सप्रेस गति से राजमार्गों का विस्तार

- 2013-14 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 92,851 कि.मी. था, जो बढ़कर 2017-18 में 1,20,543 कि.मी. हो गया
- 2017-18 में निर्माण कार्य की गति बढ़कर 27 कि.मी. प्रतिदिन हुई, जबकि 2013-14 में यह 12 कि.मी. प्रतिदिन थी

अभूतपूर्व तेजी, व्यापकता और सुरक्षा से रेल विकास

- 2017-18 में बड़ी रेल दुर्घटनाओं में 62% की कमी आई और 73 दुर्घटनाएं हुईं, जबकि 2013-14 में यह 118 थी
- 2013-14 में 2,926 किलोमीटर ट्रैक नवीनीकरण की तुलना में 2017-18 में यह लगभग 50% बढ़कर 4,405 किलोमीटर हुआ
- 2009-14 के बीच 5 वर्षों के दौरान 7,600 कि.मी. ब्रॉड गेज लाइन की तुलना में अप्रैल 2014 से मार्च 2018 के बीच 4 वर्षों में 9,528 किलोमीटर ब्रॉड गेज लाइन शुरू की गई

हवाई यातायात बढ़ा

- देश में पहली बार ए.सी. रेलगाड़ियों की तुलना में ज्यादा लोगों ने हवाई जहाज से यात्रा की
- 2017 में पहली बार घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 10 करोड़ से अधिक रही
- स्वतंत्रता के बाद 75 हवाई अड्डों पर परिचालन होता था, लेकिन दिसंबर 2016 से बाद की छोटी अवधि में ही 'उड़ान' कार्यक्रम के तहत 25 और हवाई अड्डों पर परिचालन शुरू हुआ

जलमार्गों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी

- पिछले 30 वर्षों में केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, लेकिन 2014 से 106 अतिरिक्त अंतर्देशीय जलमार्ग जोड़े गए

ग्रामीण सड़क निर्माण की गति

2013-14	2017-18
69 कि.मी.प्रतिदिन	134 कि.मी. प्रतिदिन

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क

2013-14	2017-18
92,851	1,20,543

रेलवे ट्रैक नवीनीकरण

2013-14	2017-18
2,926 कि.मी.	4,405 कि.मी.

जलमार्ग

1984-14	2014-18
5	106

हवाई अड्डों पर परिचालन

1947-16	2016-18
75	25

स्वच्छ भारत मिशन से स्वच्छता क्रांति आई

- पिछले 4 वर्षों में 7.25 करोड़ ग्रामीण आवासों में शौचालय बनाए गए जबकि 1947 से लेकर 2014 तक 6.5 करोड़ ग्रामीण आवासों में शौचालय बनाए गए थे
- स्वच्छता कवरेज 2014 में 38.70% से बढ़कर 83.71% हुई
- 11.21 लाख सरकारी स्कूलों में सभी 13.77 करोड़ बच्चों के लिये अब शौचालय की सुविधा है

करोड़ों एल.ई.डी. बल्ब बांटे गए, लोगों को अरोबों रुपये की बचत हुई

- मात्र 4 वर्षों में 29.83 करोड़ से अधिक एल.ई.डी बल्ब वितरित किए गए, लोगों के लिए 15,497 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत

करोड़ों लड़कियों का आर्थिक भविष्य सुरक्षित

- बालिकाओं के लिए 1.26 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गये, जिनमें 19,183 करोड़ रुपये जमा कराए गए

गांवों में अभूतपूर्व रूप से डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी

- 2014 के केवल 83,000 सामान्य सेवा केंद्रों (सी.एस.सी) की तुलना में अब 2.92 लाख सी.एस.सी हैं
- 2014 से 2018 तक 1.15 लाख ग्राम पंचायतों में उच्च गति ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा पहुंची, जबकि 2011 से 2014 तक केवल 59 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा थी

उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रत्येक भारतीय परिवार के लिए धुआं मुक्त जीवन सुनिश्चित

- 3.8 करोड़ गरीब महिलाओं को निःशुल्क एल.पी.जी कनेक्शन प्रदान किए गए, लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से सुरक्षित गर्भावस्था को जन आंदोलन बनाना

- 1.16 करोड़ से अधिक प्रसवपूर्व जांच की गईं

मुद्रा उद्यमी व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा कर रहे हैं

- 12 करोड़ से अधिक छोटे उद्यमियों को लाभ मिला

दिव्यांगों के लिए शिविरों में अत्यधिक बढ़ोतरी, इससे पहले उनकी ऐसी देख-भाल कभी नहीं की गई

- 2014 से दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण वितरित करने हेतु 6,000 से अधिक शिविर लगाए गए, जबकि इससे पहले के 20 वर्षों की अवधि में केवल 55 शिविर आयोजित किए गए थे

करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ावा देना

- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण हुआ
- सौभाग्य के जरिए 31 दिसंबर 2018 तक 4 करोड़ गैर-विद्युतीकृत आवासों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करना

किसानों की आय दोगुना करना, करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव लाना

- खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या एम.एस.पी में काफी बढ़ोत्तरी, उत्पादन लागत के 1.5 गुना
- पहले के 35% के विपरीत अब 100% नीम लेपित स्वदेशी यूरिया
- 87.5 लाख किसानों और विक्रेताओं के पंजीकरण वाली 417 मंडियों के माध्यम से ई-नाम पर 41,591 हजार करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद का लेन-देन
- 12.68 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित
- 2018-19 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 11 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड उच्च स्तर तक पहुंचा

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

- अगले 3 वर्षों में ऐसे 300 रुर्बन क्लस्टर बनाना

सरकार में विश्वास लगभग दोगुना हुआ, कर अनुपालन में उल्लेखनीय वृद्धि

- वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 6.84 करोड़ आयकर रिटर्न (आई.टी.आर) दाखिल किए गए, जो वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 80.5% अधिक है

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से खाते में धन पहुंचना सुनिश्चित हुआ, बिचौलिये हटे

- पिछले 4 वर्षों में 431 योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे 3,65,996 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत

मिशन इंद्रधनुष, बच्चों की देखभाल का जन आंदोलन

- 528 जिलों में 3.15 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया गया

राष्ट्र के प्रत्येक कोने में गरीबों तक सस्ती दवाएं पहुंचना

- सस्ती दवाओं के लगभग 3,000 जन औषधि केंद्रों के परिणामस्वरूप आम लोगों को सस्ती दरों पर दवाऐं जिससे उन्हें लगभग 50% की बचत हुई

विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम 'आयुष्मान भारत'

- इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों (50 करोड़ लाभार्थी) को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान की जाएगी

मात्र 4 वर्षों में प्रत्येक परिवार का एक बैंक खाता

- 31.52 करोड़ जन-धन खाते खोले गए, लगभग प्रत्येक परिवार का एक बैंक खाता है

जन सुरक्षा के जरिए 4 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा को पूरे देश में सुनिश्चित करना

- 19 करोड़ से अधिक लोगों का जीवन और दुर्घटना बीमा तथा पेंशन सुनिश्चित की गई

असाधारण तेजी से कर संरचना में ऐतिहासिक बदलाव किए गए

- एक करोड़ से अधिक करदाता जी.एस.टी के तहत पंजीकृत। पहले 65 लाख पंजीकृत करदाता थे

विश्वभर के देश भारत में निवेश करते हैं

- मौजूदा सरकार के गठन के बाद से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 47% बढ़ गया है। 2013-14 में 36.05 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2016-17 में यह 60.08 बिलियन डॉलर हो गया

कारोबार करने में सुगमता की रैंकिंग में सबसे अधिक उछाल

- कारोबार करने में सुगमता में भारत की रैंकिंग में 42 अंको की बढ़ोत्तरी हुई है जिससे यह 2014 में 142 की तुलना में 2018 में यह 100 हो गई

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में शतक बनाया

- भारत ने एक बार में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया